Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

बिहार में महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में मनरेगा की भूमिकाः नवादा जिला के विषेष संदर्भ में।

संजीव कुमार

शोध प्रज्ञ, अर्थशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय , बोधगया (बिहार)

Article Info

Publication Issue :
May-June-2023
Volume 6, Issue 3
Page Number : 20-24
Article History
Received : 07 May 2023
Published : 29 June 2023

प्रस्तावनाः— गाँव में अदृश्य अकुशल बेरोजगारी को दूर करने के गाँव से शहर की ओर पलायन रोकने तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों में रोजगार मुहैया कराकर ग्रामीण विकास व खासकर पिछड़े व गरीब वर्ग की महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में यह महत्वकांक्षी योजना मनरेगा 2 फरवरी 2006 से भारत के 200 जिलों में आरम्भ किया गया। वर्त्तमान में यह भारत के सभी 600 जिलों में क्रियान्वित है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर गरीब तबके व बेसहारों, वृद्वए निःशक्त महिला—पुरूषों की आय में वृद्धि कर ही रहा है। साथ ही गाँव में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ हैं। जिससे कर ग्राम्य अर्थव्यवस्था की संरचना मजबूत होती जा रही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक आधार मिला है।

समस्या का चयनः— यद्पि मनरेगा कार्यक्रम 2006 से क्रियान्वित हुआ है। लेकिन इसके क्रियान्वयन के बावजूद भी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाकर स्वावलंबी कैसे बनाया जाय? हमारा उद्देश्य यह भी देखना है कि मनरेगा योजना के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो सकेगी?

अध्ययन का उद्देश्यः— ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के साथ—साथ ग्रामीण महिला रोजगार रोजगार सृजन के माध्यम से स्वावलंबी आत्मनिर्भर महिला के जीवन में क्या—क्या बदलाव मनरेगा योजना ला रहा है।

कार्य प्रणालीः— प्रस्तावित अध्ययन में मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्विवितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक तौर से समस्या को सामने प्रकट करने का प्रयास किया गया है। उद्देश्यपूर्ण चयन पद्धति के तहत खुले प्रश्नों के साथ प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है। उचित उपयोग सामग्री के तहत साहित्य की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में शामिल किया जाएगा।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बिहार शायद देश का पहला राज्य होगा जहाँ शिक्षा, रोजगार एवं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिसका जीता जागता प्रमाण नवादा जिला अंतर्गत लोहरपुरा पंचायत की मुखिया बीना देवी अपने अतुलनीय कार्यों के कारण राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। इसके अलावा बिहार राज्य की दो महिला पंचायत समिति सदस्य को प्रशिक्षण के लिए यूएनओ भेजा गया। बिहार में यद्यपि महिला साक्षरता दर बढ़ने से भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न इत्यादि घृणित कुकृतियों में कमी आई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा में परिवर्तन की जरूरत है। इस क्षेत्रों में आरक्षण के बल पर पंचायती राज के पदों पर एवं रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में आमूलचूल परिवर्तन के साथ वृद्वि हुआ है। किन्तु जागरूकता एवं इच्छाशक्ति के आभाव में इनके अधिकारें का निष्पादन इनके प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता रहा है। समाज राज्य एवं राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को विशेष कर गाँव देहात की महिलाओं को हर हाल में आगे आना होगा, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ—साथ हमें स्वयं की

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

परंपरावादी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। और हम सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के सर्वागीण विकास के क्षेत्र में मनरेगा योजना एक महती भूमिका निभा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। मनरेगा के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों, कमजोर ग्रामीण में विशेषकर महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। जिससे उनमें आत्मविश्वास, रोजगार की उपलब्धता से आत्मनिर्भरता का भाव आया है, जिससे महिलाओं की क्रय क्षमता में इजाफा हुआ है। जागरूकता बढ़ी है परिवार भी सुरक्षित हुए है, सामाजिक समस्याएँ भी कम हुई है।

साहित्यावलोकनः– पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने का एक सैद्वांतिक समाधान था। अमित भादुरी (2005) ने रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से संर्पूण विकास की रूपरेखा को सैद्वांतिक तौर पर स्थापित करने की कोशिश किया है। (1997) ने ट्रांसफर इफेक्ट तथा स्टेबलाइजेशन इफेक्ट के रूप में वार्णित किया है। ट्रासफर इफेक्ट का अर्थ आमदनी में विशुद्व वृद्वि से है, तथा स्टेबलाईजशन इफेक्ट का अर्थ विपरीत परिस्थितियों में अतिरिक्त आमदनी से मिले लाभ से है। विभिन्न सर्वेक्षण एवं अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण सड़कों तथा कृषि उत्पादकता में वृद्वि का गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लोक निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का पुनः निर्माण किया जा सकता है। और जिसका कृषि एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। नारायण, पारिख एवं श्रीनिवासन, (1999) एडुआर्डो जपेदा (2012) ने दोनों अपने आलेखो में मनरेगा कार्यक्रम के फायदे तथा गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव के असर का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए इस निष्कर्ष निकाला हैं कि रोगार सृजन करने का एक बेहतर कार्यक्रम है।

भारत एक कल्याकारी देश है जो सामान्य रूप से अपने सभी नागरिकों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के प्रति प्रतिबद्व है। इसी वजह से सरकार देश के सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से निर्धन एवं ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित कर रही है। मनरेगा मनरेगा उन्ही विभिन्न योतनाओं में महत्वकांक्षी योजना है। यह अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य में कितनी सफल रही? क्या उनका अपेक्षित प्रभाव हुआ है? यह उनकी क्रियान्वित में क्या समस्याएं आ रही है? उनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए? यह शोध का विषय है।

इस लेख में बिहार तथा नवादा जिले में मनरेगा के अंतर्गत हुई प्रगति एवं महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है अध्ययन की अवधि योजना मार्च से 2018 से दिसम्बर 2022 तक ली गई है। आंकड़े मुख्यतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत बिहार प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण पत्रिकाओं तथा मनरेगा की वेबसाइट **www.nrega.nic.in** द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

मनरेगा योजना के मुख्य बिन्दुः– मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के व्यस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करने का इच्छा रखता है। उनहें रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के रोजगार की कानूनी गारंटी दिया गया है। इसके अधीन पंजीकृत परिवार का व्यस्क सदस्य अकुशल मानव श्रम के लिए आवेदन करने का पात्र है। इसके जॉब कार्ड जारी होने पर रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है। मजदूरी श्रम आयुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के निर्धारित दर से देने का प्राधान है। रोजगार की मांग की तारीख से 15 दिनों में रोजगार पाने का अधिकारी हो जाता है। और यह भत्ता राज्य सरकार को वहन करना होता है। योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। कार्यस्थल पर तात्कालिक उपचार की सुविधा, पेयजल, छां‹ के लिए शेड, शिशु के लिए पालना आदि उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। योजना के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में 25000 बतौर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। योजना में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

मनरेगा में वित्तीय प्रबंधनः– मनरेगा योजना में वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा मजदूरी की पूरी राषि, सामग्री की लागत की तीन चौथाई राषि तथा प्रषासनिक खर्चों के लिए कुल लागत का तय किया गया प्रतिषत उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता सामग्री लागत की एक चौथाई राषि और राज्य परिषद का प्रषासकीय खर्च उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

बिहार में मनरेगा की प्रगतिः– मनरेगा एक माँग आधारित योजना है जिसके अन्तर्गत जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, वानिकी वृक्षारोपन, भूमि विकास, सड़कों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण व संरक्षण अपनाए जाने की व्यवस्था है। विभिन्न वर्षों में मनरेगा की रिर्पोट दर्शाया गया है।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत बिहार में सन् 2018–19 में जॉबकार्ड जारी किए गए कुल परिवारों की संख्या 15775888 थी जो सन् 2021–22 में बढ़कर 20755994 हो गई। पुनः 2018–19 में रोजगार उपलब्ध कराए गए महिलाओं की संख्या 1727888 थी जो 2021–22 में बढ़कर 2856343 हो गई।

2018–19 में कुल सृजित रोजगार मानव विकास दिवस में कुल 123180192 था जिसमें महिला मानव दिवस 63735312 था जो 2021–22 में बढ़कर कुल रोजगार मानव दिवस 180848012 हुआ जिसमें महिला मानव दिवस 963182097 हुआ। 2018–19 में 100 दिवस पूरा करने वाले कुल परिवारों की संख्या 24548 था जो 2021–22 में घटकर 21807 हो गई ।

बिहार में मनरेगा में रोजगार स्थिति

वर्ष	जारी किए गए जॉबकार्ड की कुल सं०	रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं०		कार्य दिवस		100 दिवस पूरा किए गए परिवारों की सं०
		कुल	महिला	कुल	महिला	
2018-19	15775888	2919078	1727888	123180192	63735312	24548
2019-20	17105052	3363507	2104323	1413363980	78952691	20366
2020-21	19317696	5087969	3046568	207217796	124125914	35047
2021-22	20755994	4791331	2856343	180848012	96182097	21809

स्त्रोतः– MIS Report

ग्रामीण विकास विभाग, 11 मार्च 2023

www.narega.nic.in

नवादा जिले में मनरेगा योजना की प्रगतिः– नवादा जिले में मनरेगा योजना की प्रगति को दर्शाता है। नवादा जिले में मनरेगा के अन्तर्गत जारी किए गए जॉबकार्ड परिवारों की संख्या 462192 था जो 2021–22 में बढ़कर 549223 हो गया है।

2018–19 में रोजगार प्राप्त कुल परिवार की संख्या 98208 था जिसमें 61151 थी जो 2021–22 में क्रमशः 117707 व 68791 हो गया है। नवादा जिले में वर्ष 2018–19 में कुल रोजगार मानव दिवस 4734123 था जिसमें महिला मानव दिवस 2652968 था जो वर्ष 2021–22 में घटकर क्रमशः 4506149 व 242411 हो गया। नवादा जिले में वर्ष 2018–19 में 100 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार की कुल संख्या 1540 था जो 2021–22 में घटकर 950 हो गया।

नवादा जिला में मनरेगा में रोजगार स्थिति

वर्ष	जारी किए गए जॉबकार्ड की कुल सं०	रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं०		कार्य दिवस		100 दिवस पूरा किए गए परिवारों की सं०
		कुल	महिला	कुल	महिला	
2018-19	462192	98208	61151	4734123	2652968	1540
2019-20	483459	86031	52467	3593079	1924461	869
2020-21	523759	101190	59119	4636939	2454718	1585
2021-22	549223	117707	68791	4506149	2424118	950

स्त्रोतः– MIS Report

ग्रामीण विकास विभाग, 11 मार्च 2023

www.narega.nic.in

नवादा जिले में मनरेगा में कार्य निष्पादन स्थिति का विवरणः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मनरेगा के अन्तर्गत कुल प्रगतिरत 91580 कार्य था जिसमें से कुल 85425 कार्य का पूर्ण किये गये जो कुल कार्य का 93.28 प्रतिशत था। और 2021–22 में घटकर प्रगतिरत कुल कार्य 10978 हो गया जिसमें से कुल 6465 कार्य पूर्ण हुए जो कुल कार्य का 58.89 प्रतिशत था। आंकड़े इस बात का साक्षी है कि मनरेगा में जो कार्य चल रहे है उसमें निरंतर कमी हो रही है।

नवादा में मनरेगा में रोजगार स्थिति विवरणी

वर्ष	शुरू किये गए कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गये कार्यों की सं०	अभी तक पूरा नही हुए कार्यों की सं०	कार्य पूर्ण होने की दर प्रतिशत में
2019-20	91580	85425	6155	93.28
2020-21	10978	6465	4513	58.89
2021-22	12778	6486	6292	50.76

स्त्रोतः– MIS Report

ग्रामीण विकास विभाग, 11 मार्च 2023

www.narega.nic.in

निष्कर्ष एवं चुनौतियाँः– अदृश्य मौसमी और ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने, क्षेत्र का विकास करने की अद्भुत महत्वकांक्षी व्यापक वित्तीय योजना मनरेगा अपने अद्देश्य को प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल रही है। जैसा कि संपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में इस योजना में उपलब्धियों का ग्राफ ऊपर की ओर गया हैं वहीं बिहार राज्य में उपलब्धियों का ग्राफ नीचे की ओर गया है। इस योजना में पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखना आवश्यक है। और यह योजना अपने स्वर्णिम लक्ष्यों को हासिल कर सकेगी। अंत में हम कहना चाहते हैं कि समाज राज्य एवं राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को विशेषकर गाँव देहात की महिलाओं को हर हाल में आगे आना होगा, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ–साथ हमें स्वयं की परंपरावादी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। महिला

सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। मनरेगा के माध्यम से दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों, कमजोर ग्रामीण में विशेषकर महिलाओं को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। जिससे उनमें आत्मविश्वास, रोजगार की उपलब्धता से आत्मनिर्भरता का भाव आ सके। महिला लाभार्थी के सभी उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम करके उनकी आय में वृद्धि हुई है एवं महिलाओं की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे समाज के लोगों में जागरूकता बढ़ी है परिवार भी सुरक्षित हुए हैं, सामाजिक समस्याएं भी कम हुई है।

संदर्भ सूचीः–

1. डांडेकर एवं रथ (1971) पावर्टी इन इंडियाः डाइमेंशन एंड ट्रेड्स
2. कीन्स जान मेएनार्ड (1951) द जनरल थ्योरी ऑफ एंप्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी मैकमिलन एंड कंपनी लि० लंदन
3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना दिशानिर्देश 2008 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली पृष्ठ संख्या–1
4. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका रोजगार स्थिति नवम्बर 2013
5. भादुरी, अमित (2005) डेवलपमेंट विथ डिग्निटी नेशनल बुक ट्रष्ट नई दिल्ली
6. अमर्त्य सेन आर्थिक विषमताएँ राजपाल प्रकाशन नई दिल्ली (2008)